प्रेस विज्ञप्ति

2 जून, 2018। नई दिल्ली

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रभारी, संचार विभाग, अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया:-

सड़कों पर उतरे विवश किसान, नहीं मिलते उन्हें फसलों के उचित दाम
निर्मम भाजपा को है सिर्फ सुर्खियों से काम
किसानों की दुर्दशा और आत्महत्या का काल - मोदी सरकार के चार साल

देश भर के 130 से अधिक किसान संगठन मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते एक से दस जून तक गाँव बंदी आंदोलन को आकार दे रहे हैं । यह पहला अवसर नहीं है कि किसानों ने भाजपा सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट किया हो। बीते चार सालों से यही हालत है। किसान खेतों की अपेक्षा सड़कों पर आंदोलित दिखाई देता है । मगर भाजपा सरकार के सत्ता के अहंकार का आलम यह है कि वो किसानों की मांगों का संज्ञान लेने की अपेक्षा कभी उनके सीने में गोलियाँ उतार देती है ,तो कभी जेलों में ठूस देती है । इससे बड़ी वेदना क्या होगी कि किसान को एक ओर अपनी फ़सलों के दाम नहीं मिल रहे, और दूसरी ओर वो विरोध प्रदर्शन के लिए यह कठोर निर्णय ले कि वह दस दिन तक अपनी उपज को बाज़ार में नहीं बेच कर अपना विरोध दर्ज़ कराएगा । इस पर भी मोदी सरकार का दिल पसीजने की अपेक्षा वो किसानों से अपराधियों की तरह बॉन्ड भरवा रही है। झूठे मुकदमें दर्ज़ कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल रही है ।

मोदी सरकार का कार्यकाल किसानों की दुर्दशा के काल के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है । निरंतर चार वर्षों से किसान मोदी सरकार से गुहार लगा रहा है कि फसलों की लागत का 50 % ऊपर समर्थन मूल्य देने का वादा जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया था उसे निभाए ।

मगर मोदी सरकार ने किसानों को धोखा देते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय में 6-2-2015 को शपथ पत्र दे दिया कि अगर स्वामीनाथन कमीशन की 'लागत का 50 % ऊपर समर्थन मूल्य' देने की सिफारिश को स्वीकार किया गया तो बाजार बिगड़ जाएगा। अर्थात मोदी सरकार किसानों की अपेक्षा जमाखोरों और बिचौलियों के पक्ष में खड़ी हो गई ।

चौंकाने वाली बात यह भी है कि मोदी सरकार ने अपने उस शपथ पत्र में सर्वोच्च न्यायालय में यह भी स्वीकार किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 14-10-2009 से 9-1-2014 तक स्वामीनाथन कमीशन की 201 सिफारिशों में से 175 सिफारिशें लागू कर दी गई हैं । जहाँ तक मोदी सरकार के लागत के 50% ऊपर समर्थन मूल्य दे देने का दावा है, तो सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है ।

उदाहरण के लिए, मूँग का लागत मूल्य 5700 रु है और समर्थन मूल्य 5575 रु । इसी तरह ज्वार का लागत मूल्य 2089 रु है और समर्थन मूल्य 1700 रु । लगभग सभी फ़सलों का यही हाल है । चाहे धान हो, गेहूँ हो,चना हो या मूँगफली, बमुश्किल लागत मूल्य किसानों को मिल रहा है ।

गन्ना किसानों की दुर्दशा का भी यही हाल है।देश के गन्ना किसानों का लगभग 20 हज़ार करोड़ रु बकाया है। मूल कारण यह है कि शक्कर के अच्छे उत्पादन के बाद भी शक्कर का भाव धराशायी हो गया है । मोदी

जी ने पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में शक्कर इम्पोर्ट करवा कर देश के गन्ना किसानों के जीवन में कड़वाहट घोल दी है।

इतना ही नहीं,किसानों के नाम पर चलाई जा रही फ़सल बीमा योजना में खरीफ़ 2016 और रबी 2016-17 में प्राइवेट कंपनियों को 14,828 करोड़ रु का लाभ मोदी सरकार ने पहुँचाया है।

किसानों की दूसरी माँग है 'कर्ज माफी'। देश भर का किसान मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। किसानों का कहना है कि 2014 - 16 के सूखे के बाद जब मानसून मेहरबान हुआ तो मोदी सरकार की मेहरबानी अनाज के बड़े व्यापारियों पर हो गई।और 2016 - 2017 में 275 मिलियन टन खाद्यान्न का अच्छा उत्पादन हुआ, जिसमें गेहूँ का 98.5 मिलियन टन और दाल का 23.13 मिलियन टन का उत्पादन हुआ, अर्थात दाल देश की आवश्यकता से भी अधिक पैदा हुई। मगर मोदी सरकार ने किसानों को धोखा देते हुए इम्पोर्ट ड्यूटी 0% तक कर सस्ता गेहूँ, लगभग 50 लाख टन और दाल 59 लाख टन, इम्पोर्ट करने की अनुमति दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप मुट्ठी भर इम्पोर्टर्स को बहुत बड़ा मुनाफ़ा हुआ और किसानों के लिए बाज़ार में फ़सलों के भाव धराशायी हो गए और किसान बर्बादी की कगार पर खड़ा हो गया।

- इसका परिणाम यह हुआ कि आज 35 से अधिक किसान रोज़ आत्महत्या करने पर मजबूर हैं।

- मोदी सरकार ने बीते चार सालों में मुट्ठी भर धन्ना सेठों का लगभग 2.41 लाख करोड़ रु का कर्ज राइट ऑफ किया है। अकेले 2017 - 18 में 53,226 करोड़ रु का कर्ज राइट ऑफ किया है। किसानों की माँग है कि मोदी सरकार जब अपने मुट्ठी भर धनपतियों का लाखों करोड़ का कर्ज माफ़ कर सकती है तो फ़िर किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ़ कर सकती। ज्ञातव्य है कि कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने किसानों का 72 हज़ार करोड़ रु का कर्ज माफ़ किया था।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी दृढ़ता और मुखरता से मोदी सरकार द्वारा किसानों के दमन का विरोध करती है।

किसानों के शांति पूर्वक विरोध के समर्थन में समूचा देश साथ खड़ा है। यह कितना हृदय विदारक है कि किसान जब अपने फ़सलों की उचित माँग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज़ करता है तो भाजपा सरकार उन्हें पास बुलाकर उनके सीने में गोलियाँ उतार देती है। यही हुआ था जून 2017 में मध्यप्रदेश के मंदसौर में 6 किसानों को भाजपा सरकार ने मौत के घाट उतार दिया था।इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी मध्यप्रदेश के मंदसौर में 6 जून को किसानों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाएंगे और देश भर के किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करेंगे।